



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 31, 2007/भाद्र 9, 1929

No. 258]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 2007/BHADRA 9, 1929

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2007

‘8.20 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022’ की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

फा. सं. 4(5)-डब्ल्यूएंडम/2007.—भारत सरकार एतद्वारा 4,000^० करोड़ रुपए(नामिनल) की कुल राशि के लिए ‘8.20 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2022’ (जिसे इसके बाद ‘स्टॉक’ कहा गया है) की बिक्री (पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे ‘विदेष्ट अधिसूचना’ कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार द्वारा जारी सारांश अधिसूचना एफ. संख्या 4(9)-डब्ल्यूएंडम/2000 दिनांक 6 मई, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी।

नीर्गम की विधि

2. सरकारी स्टॉक की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से दिनांक 6 मई, 2002 की सामान्य अधिसूचना एफ. संख्या 4(9)-डब्ल्यूएंडम/2000 के पैरा 5.1 से निर्धारित तरीके से अनेक मूल्य नीलामी विधि का प्रयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी द्वारा की जाएगी।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आवंटन

3. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न रकीम (अनुबंध) के अनुसार बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित किया जाएगा।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

4. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 7 सितम्बर, 2007 को संचालित की जाएगी। बोलियो सहित विधिवत भरे गए आवेदन-पत्र 7 सितम्बर, 2007 को अपराह्न 12.30 बजे तक उपर्युक्त कार्यालय में प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए।

कब नीर्गमित कारोबार

5. यह स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसके परिपत्र सं0 आरबीआई/2006-07/178 दिनांक 16 नवम्बर, 2006 के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ‘कब नीर्गमित’ कारोबार के लिए पात्र होगा।

अवधि

6. 15 फरवरी, 2007 से प्रारम्भ यह स्टॉक पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए होगा। स्टॉक की वापसी-आदायगी 15 फरवरी, 2022 को सम्मूल्य पर की जाएगी।

नीर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान

7. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट, मुंबई कार्यालय में 7 सितम्बर, 2007 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 10 सितम्बर, 2007 अर्थात् पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में

अधिकारित स्तर के नगरिनी गुल्मी वर्ष लालू-कुमार दुमाहार की दिनांक से उत्तर 15 अक्टूबर 2007 से 9 दिसंबर 2007 तक लपागिर व्याज शामिल होगा।

व्याज

व्याज मूल रिंग की दरीच्छा से रुपैयों के नियन्त्रित मूद्रा पर 8.20 प्रतिशत दरों के बाज उपचित होना तथा इसका मूद्रा पर अर्ह-वार्षिक आधार पर 15 फरवरी तक 15 अक्टूबर को किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से
वि. शिवमुखमण्यन, निरेशक (बजट)
अनुबंध

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी गोली सुविधा रक्षीम

I. कार्यक्षेत्र : सरकारी प्रतिभूतियों की लालू भागीदारी विरुद्ध खुल्ला वर्तित को गोलीमें देने वाली दीर्घ से भारत शरकार के दिनांकित प्रतिभूतियों वाली वयनित नीलामियों में “अप्रतिस्पर्धी” आधार पर गोलीदारी वाली अनुमति देने का प्रस्ताव किया रखा जा रहा है तदुस्तूर दिनांकित प्रतिभूतियों को नीलामियों ने अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत वर्ष की अप्रतिस्पर्धी दैसियां स्वीकृत की जाएंगी प्रारक्षित राशि अधिसूचित राशि के अन्तर्गत जाएंगी।

II. पात्रता : भारत शरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी आधार पर ऐसा नियोजकों द्वारा नीलामी खुली दी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं।

1. जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास वालू खाता (रीए) भारत अद्याहुत रामयन, वही (एसआरएल) खाता नहीं रखते हैं।

अपवाद : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और लड़कारी बैंकों का वालू राजनीतिक दैवित्यों के वृष्टिमान इस रक्षीम के अधीन शामिल किया जाएगा।

2. जो प्रति नीलामी दो करोड़ रुपए (अंकत मूल्य) से अधिक राशि के लिए एक इंग गोली लगाते हैं।

3. जो यह रक्षीम प्रयोग बनाए जाते हैं तो वही एक बैंक अधार प्रायमिक नीलामी मूल्यमें से अपनी गोली अप्रतिस्पर्धी आधार प्रस्तुत करते हैं।

अपवाद : ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा लड़कारी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक में एसआरएल खाता और वालू खाता रखते हैं, अपने अप्रतिस्पर्धी दैसियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

III. व्यापकता : उपर्युक्त शर्तों के अंतर्गत “अप्रतिस्पर्धी” पात्रता पर छह, एकूण गोली, नियमित नियमों गतियां भी अप्रतिस्पर्धी वालू और भारतीय नियमित नियमों के अन्य नियमों वालू वाली गोली वर्षों के लिए नीलामी दी जाती है। गोली देने वाली न्यूनतम राशि 10.00 रुपए (एकूण मूल्य) वालू वाली वर्षों के गोली वालू वाली दिनांकित स्वीकृत के लिए है।

IV. अन्य प्रचालनात्मक विशानिये :

- खुदरा नियोजक के लिए उस दैवित्यों वाली वार्षिक गोली, नियमित नियमों गतियां भी अप्रतिस्पर्धी वालू और भारतीय नियमित नियमों के अन्य नियमों वालू वाली गोली वर्षों के लिए नीलामी दी जाती है। इस अन्यद के अन्तर्गत नियमित नियमित नियमों वालू वाली वर्षों के गोली वालू वाली दिनांकित स्वीकृत के लिए है।
- अपने ग्राहकों से प्राप्त पक्के आड़ेर पर प्रत्येक वैक अथवा प्रायमिक डीलर एनडीएस के जरिए आवेदन वार वैलियां प्रस्तुत करेगा। अन्य लोगों (अथवा गैर ग्राहकों) से प्राप्त पक्के आड़ेरों को प्रायमिक डीलर कार्यालय में वारताविक आवेदन प्रपत्रों में प्रस्तुत किया जाए। वारताविक आवेदन सभी ग्राहकों की समग्र राशि के लिए एक एकल वार्ती हो सकती है। अलग अलग ग्राहकों का व्यौरा यथा नाम और राशि गोली के अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

3. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर को अप्रतिरक्षित खंड के अधीन आबंटन प्रतिलाभ/कीमत की उस भारांशित औसत दर पर होगी, जो प्रतिरक्षित बोली देने के आधार पर नीलामी में सामने आएगी। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बैंक अथवा प्राथमिक डीलर ने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर लिया है या नहीं, निर्गम की तारीख को भुगतान प्राप्त करके बैंक या प्राथमिक डीलर को प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी।
4. ऐसे मामले में, जहां बोली की राशि प्रारक्षित राशि (अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत) से अधिक है यथानुपात आबंटन किया जाएगा। आंशिक आबंटनों के मामले में, यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियों का उचित आबंटन एक पारदर्शी तरीके से करें।
5. ऐसे मामले में जहां बोली राशि प्रारक्षित राशि से कम हो, कमी को प्रतिरक्षित भाग में लिया जाएगा।
6. प्रतिभूति लो-भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल एसजीएल रूप में जारी किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इसे या तो बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के मुख्य एसजीएल खाते अथवा सीएसजीएल खाते में जमा करेगा, जैसाकि उनके द्वारा निर्देश दिया गया है। मुख्य एसजीएल खाते में जमा करने की सुविधा एकमात्र उन निवेशकों की सेवा के प्रयोजनार्थ है जो उनके घटक नहीं हैं। अतः बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों को अप्रतिरक्षित बोलियों की निविदा देते समय उनके एसजीएल खाते और सीएसजीएल खाते में जमा होने वाली राशियों (अंकित मूल्य) को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। बाद में निवेशक के अनुरोध पर मुख्य एसजीएल खाते से वास्तविक रूप में की गई सुपुर्दगी रखीकार्य है।
7. यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलर का उत्तरदायित्व है कि वह ग्राहक को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करें। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, ग्राहकों को प्रतिभूतियों का अंतरण निर्गम की तिथि से पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।
8. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर अपने ग्राहकों को यह सेवा देने के लिए छह पैसे प्रति सौ रुपए तक दलाली/कमीशन/सेवा प्रभार के रूप में वसूल कर सकते हैं। ऐसी कीमत विकी मूल्य में शामिल की जा सकती है या ग्राहकों से अलग से वसूल की जा सकती है। ऐसे मामले में जहां प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूति की निर्गम तिथि के बाद प्रभावी होता हो, बैंक या प्राथमिक डीलर को ग्राहक द्वारा देय प्रतिफल राशि में निर्माण तिथि से उपचित ब्याज शामिल होगा।
9. प्रतिभूतियों की लागत, उपचित ब्याज जहां भी लागू हो, तथा दलाली/कमीशन/सेवा प्रभारों के लिए ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली, बैंक या प्राथमिक डीलर द्वारा ग्राहक के साथ की गई सहमति के अनुसार तैयार की जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि कोई अन्य लागत, जैसे निधिकरण लागत को मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए या ग्राहकों से वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

V. बैंकों और प्राथमिक डीलरों को भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) द्वारा समय-समय पर मांगी गई योजना के तहत रांचालनों से संबंधित सूचना निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।

VI. ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देश बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन है और तदनुसार जब भी आवश्यकता होगी, योजना को संशोधित किया जाएगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2007

Auction for Sale (Re-issue) of '8.20 per cent Government Stock, 2022'

F. No. 4(5)-W&M/2007.—Government of India hereby notifies sale (re-issue) of '8.20 per cent Government Stock, 2022' (hereinafter called 'the Stock') for an aggregate amount of Rs. 4,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification') as also the terms and conditions specified in the General Notification F No.4 (9)-W&M/2000, dated May 6, 2002 issued by Government of India as amended from time to time.

Method of Issue

2. The Stock will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai- 400 001 in the manner as prescribed in paragraph 5.1 of the General Notification F No.4 (9)-W&M/2000, dated May 6, 2002 by a price based auction using multiple price auction method.

Allotment to Non-competitive Bidders

3. The Government Stock up to 5 per cent of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions as per the enclosed Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities (Annex).

Place and date of auction

4. The auction will be conducted by Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on September 7, 2007. The application form duly filled in with the bids should be submitted to the aforesaid office on September 7, 2007, by 12.30 P.M.

When Issued Trading

5. The Stock will be eligible for "When Issued" trading in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India in its circular No.RBI/2006-07/178 dated November 16, 2006.

Tenure

6. The Stock will be of fifteen -year tenure commencing from February 15, 2007. The stock will be repaid at par on February 15, 2022.

Date of issue and payment for the Stock

7. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its Fort, Mumbai office on September 7, 2007. The payment by successful bidders will be on September 10, 2007, i.e., the date of re-issue. The payment for the Stock will include accrued interest on the nominal value of the Stock allotted in the auction from the date of last coupon payment, i.e., August 15, 2007 to September 9, 2007.

Interest

8. Interest at the rate of 8.20 per cent per annum will accrue on the nominal value of the Stock from the date of original issuance and will be paid half yearly on February 15 and August 15.

By Order of the President of India
V. SIVASUBRAMANIAN, Director (Budget)

Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities

I. Scope: With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government securities it is proposed to allow participation on “non-competitive” basis in *select* auctions of dated Government of India (GOI) securities. Accordingly, non-competitive bids *up to 5 per cent* of the notified amount will be accepted in the auctions of dated securities. The reserved amount will be **within** the notified amount.

II. Eligibility: Participation on a non-competitive basis in the auctions of dated GOI Securities will be open to investors who satisfy the following:

1. do not maintain current account (CA) or Subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India.

Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks shall be covered under this Scheme in view of their statutory obligations.

2. make a *single* bid for an amount not more than Rs. two crore (face value) per auction.

3. submit their bid *indirectly* through any *one* bank or PD offering this scheme.

Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks that maintain SGL account and current account with the Reserve bank of India shall be eligible to submit their non competitive bids directly.

III. Coverage: Subject to the conditions mentioned above, participation on “non-competitive” basis is open to any person including firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts, and any other entity as may be prescribed by RBI. The minimum amount for bidding will be Rs. 10,000 (face value) and thereafter in multiples in Rs. 10,000 as hitherto for dated stocks.

IV. Other Operational Guidelines:

1. It will *not* be mandatory for the retail investor to maintain a constituent subsidiary general ledger (CSGL) account with the bank or PD through whom they wish to participate. However, an investor can make only a single bid under this scheme. An undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to be obtained and kept on record by the bank or PD.

2. Each bank or PD on the basis of firm orders received from their constituents may submit application -wise bids through NDS. The firm orders received from others (i.e. non-constituents) may be submitted in physical application forms to the PDO. The physical application may be a single bid for the aggregate amount of all the customers. Particulars of individual customer viz. name and amount shall be provided as an Annex to the bid.

3. Allotment under the non-competitive segment to the bank or PD will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the bank or PD against payment on the date of issue irrespective of whether the bank or PD has received payment from their clients.

4. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5% of notified amount), pro rata allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.

5. In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion.

6. Security would be issued *only* in SGL form by RBI. RBI would credit either the main SGL account or the CSGL account of the bank or PD as indicated by them. The facility for affording credit to the main SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents. Therefore, the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the non-competitive bids the amounts (*face value*) to be credited to their SGL account and the CSGL account. Delivery in physical form from the main SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently.

7. It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients. Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the clients shall be completed within *five* working days from the date of issue.

8. The bank or PD can recover upto six paise per Rs100 as brokerage/comission/service charges for rendering this service to their clients. Such costs may be built into the sale price or recovered separately from the clients. In case the transfer of securities is effected subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the bank or PD would also include accrued interest from the date of issue.

9. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest wherever applicable and brokerage/commission/service charges may be worked out by the bank or PD as per agreement with the client. It may be noted that no other costs such as funding costs should be built into the price or recovered from the client.

V. Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank.

VI. The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified.

अधिसचिना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2007

‘8.33 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2036’ की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

फा. सं. 4(5)-डल्ल्यूएंडएम/2007(i).—भारत सरकार अनुद्देश्य वर्तमान वर्ष (नवमीनवे) की कुल राशि के लिए 18.23 प्रतिशत भरकारी रेट्रॉक 2036 (जिसे इसके बाद 'रेट्रॉक' कहा जाता है) की दरी उपर्याप्त अविश्वसित करती है यह तिथि इस अधिगृह्यता (जिसे 'टिश्विल' अधिसूचना कहा जाता है) से उत्तराधिकारी दिनों के अनुसार अनुमान दिया गया अवधारणाएं पर भारत सरकार द्वारा जारी समाचार अधिसूचना एफ.संख्या 4(5)-डल्ल्यूएंडएम/2000 द्वारा 1 अगस्त 2002 में जिवेत हाई को खोली जाएगी।

निर्गम की विधि

2. सरकारी रुक्क की विक्री भवित्वे दिनों तैर, नूरई कार्यालय, एवं सरकारी वित्ती विभागों द्वारा दिनांक 6 मई, 2002 की तिथि अधिसूचना एवं रख्ता 4(७)-डिस्ट्रिक्ट/2002 के दैर 5.1 में निर्दिष्ट रूपों में त्रिपुरा गृह नीलमी विधि का प्रयोग करते हुए गृह आधारित नीलमी दाता की जाएगी।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

3. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

नीलामी का रथान एवं तारीख

4. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 7 सितम्बर, 2007 को संचालित की जाएगी। बोलियों सहित विधिवत भरे गए आवेदन-पत्र 7 सितम्बर, 2007 को अपराह्न 12.30 बजे तक उपर्युक्त कार्यालय में प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

5. यह स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसके परिपत्र सं0 आरबीआई/2006-07/178 दिनांक 16 नवम्बर, 2006 के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

अवधि

6. 7 जून, 2006 से प्रारम्भ यह स्टॉक तीरु वर्ष की अवधि के लिए होगा। स्टॉक की वापसी-अदायगी 7 जून, 2036 को सममूल्य पर की जाएगी।

निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान

7. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट, मुंबई कार्यालय में 7 सितम्बर, 2007 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 10 सितम्बर, 2007 अर्थात् पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित स्थान के नामिनल मूल्य पर अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से अर्थात् 7 जून, 2007 से 9 सितम्बर, 2007 तक उपचित ब्याज शामिल होगा।

ब्याज

8. प्रारम्भिक निर्गमन की तारीख से स्टॉक के नामिनल मूल्य पर 8.33 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज उपचित होगा तथा इसका भुगतान अर्द्ध-वार्षिक आधार पर 7 दिसम्बर तथा 7 जून को किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से
वि. शिवसुब्रमण्यन, निदेशक (बजट)
अनुबंध

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा स्कीम

I. कार्यक्षेत्र : सरकारी प्रतिभूतियों की क्षापक भागीदारी और खुदरा धारिता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की चयनित नीलामियों ने "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की अप्रतिस्पर्धी बोलियां रखीकार की जाएंगी। प्रारम्भिक राशि के अन्तर्गत होंगी।

II. पात्रता : भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी आधार पर ऐसे निवेशकों के लिए भागीदारी खुली होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं :

1. जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाता (सीए) अथवा सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता नहीं रखते हैं, अपवाद : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को उनके सांविधिक दायित्वों के दृष्टिगत इस स्कीम के अधीन शामिल किया जाएगा।
2. जो प्रति नीलामी दो करोड़ रुपए (अंकित मूल्य) से अनधिक राशि के लिए एक ही बोली लगाते हैं, 3. जो यह स्कीम प्रदान करने वाले किसी एक बैंक अथवा ग्रामीण बैंक के माध्यम से अपनी बोली अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं। अपवाद : ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा सहकारी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक मे एस.जी.एल.खाता और चालू खाता रखते हैं, अपनी अप्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

III. ज्यापकता : उपर्युक्त शर्तों के अधीन "अप्रतिस्पर्धी" आधार पर फर्मों, कंपनियों, निगमित निकायों, संस्थाओं, भविष्य निधियों, न्यासों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा-निर्धारित किसी अन्य कंपनी सहित किसी भी व्यक्ति के लिए भागीदारी खुली

है। बोली देने की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए (आकेता गूल्हा) और उसके बाद 10,000 रुपए के पुण्यजी में होगी जैसा अब तक दिनांकित रटेंक के लिए है।

IV. अन्य प्रचालनात्मक दिशानिर्देश :

- खुदरा निवेशक के लिए उस बैंक अथवा प्राथमिक डीलर जिनके मध्यम से हम उन्हें कहते हैं, के पारा एक राधिक सहायक सामान्य बही (सीएसपीएल) खाता रखना अनिवार्य नहीं होगा। तथाहि कहें गा। निवेशक इस सर्कीम के अधीन केवल एक बोली दे सकता है। इस आशय का बाबन कि निवेशक केवल एक बोली दे सकता है। बैंक अथवा प्राथमिक डीलर द्वारा प्राप्त किया जाना और रिकार्ड में रखा जाना। आवश्यक होगा।
- अपने ग्राहकों से प्राप्त पतके आर्डर के आधार पर प्रत्येक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर एनडीएस के जरिए आवेदन भार बोतियां प्रस्तुत करेगा। अन्य लोगों (अर्थात् गेर-ग्राहकों) से प्राप्त पतके आर्डरों को प्राथमिक डीलर कार्यालय में वास्तविक आवेदन प्रपत्रों में प्रस्तुत किया जाए। वास्तविक आवेदन सभी ग्राहकों की समग्र राशि के लिए एक एकल बोली हो सकता है। अलग-अलग ग्राहकों का ब्यौरा यथा नाम और राशि बोली के अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
- बैंक अथवा प्राथमिक डीलर को अप्रोतोसार्व संह के अधीन अखेलन प्रतिलिपि के मात्र की उस भासाशीत औसत दर पर हीनों जो प्रतिरोधी बोली देने के आधार पर नीतानि में सम्पन्न आएगी। इस बात पर ध्यान दिए रिंग कि बैंक अथवा प्राथमिक डीलर ने अपने ग्राहकों से गुणतान प्राप्त कर लिया है कि नहीं निर्गत की उसीसे तो गुणतान प्राप्त बत्तक बैंक या प्राथमिक डीलर को प्रतिभूतियों जारी की जाएगी।
- ऐसे मामले में, जहां दोली की राशि प्रारक्षित राशि (अधिसूचित राशि के ८ प्रतिशत) से अधिक है यथानुपारा अखेलन किया जाएगा। आंशिक आवंटनों के मामले में यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों ने उत्तरदायित होगा कि वह अपने ग्राहकों को प्रतिभूतियों का उचित आवंटन एक पासदर्शी तरीके से करें।
- ऐसे मामले में जहां बोली राशि प्रारक्षित राशि से कम हो, कगी को प्रतिस्पृही नाम न दिया जाएगा।
- प्रतिशूलि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल एसजीएल रूप से जारी किया जाएगा भारतीय रिंग बैंक द्वारा दीर्घ अवधि के लिए एसजीएल रूप से अशा सोनार्जीएल राशि में नाम करेगा। उसके लिए गुण निर्देश दिया जाएगा। इस मुख्य एसजीएल राशि में जहां करने के साथ-साथ इकमात्र उस निवेशकों की जिका के अंतर्बोनार्थ है जहां उनके घटक नहीं हैं। अल्ला बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों के अंतर्गत वे विविध देशों सम्म एसजीएल राशि और सीएसपीएल खाते में जमा होने वाली राशियों (अंकुर गुल्फ) को साप्ट रूप से वर्णित की जाती है। इस मामले में निवेशक के समुदाय पर मुख्य एसजीएल खाते से वास्तविक रूप में की वह गुणिती रर्टिकार्ड है।
- यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलर का उत्तरदायित है कि वह ग्राहक का प्रतिनिधित्व करता रहता है। असाधारण कर्तव्यस्थापितों के छोड़कर, ग्राहकों ने प्रतिभूतियों का अत्याधिकार नहीं दिया गया है। यह ग्राहकों के अत्याधिकार के बारे में गुण निर्देश दिया जाएगा।
- बैंक अथवा प्राथमिक डीलर अपने ग्राहकों को यह निका देने के लिए इस प्रकार दृष्टि रख लग दलाली/कर्नीशन/हैंडे, इमार के रूप में दर्शुल कर सकते हैं। ऐसी जैसी दृष्टि मुख्य में शामिल होने वाली है जो उनको से अलग से वास्तु ही नहीं सकती है। ऐसे मामले में जहां प्रतिभूतियों का अंतर्गत प्रतिशूलि के नाम अंतर्गत होता है, बैंक या प्राथमिक डीलर को ग्राहक गुण देख प्रतिफल रखने से निरोन बोधि से उत्पन्न होता है।
- प्रतिभूतियों की लागत उपयोग व्याज जहां भी लागू हो तथा दलाली/कर्नीशन/हैंडे, इमार करने की कार्य प्रणाली बैंक या प्राथमिक डीलर हाथ धारक के बाय जीव वर्ष मात्र का अनुग्राह दिया जानी चाहिए। यह उत्तरेखार्निय है कि योई अन्य लागत जैसे निवेशक राशि की वृद्धि में वर्षित वर्षीय वाय जाना चाहिए या लागत का वृद्धि नहीं किया जाना चाहिए।

V. कैरो और प्राथमिक डॉलरो के भारी पूरे रिकॉर्ड (पैक) द्वारा सम्मानित करने वाली अंतिम के रहित संयुक्त राज्य अमेरिका सम्पन्न विदेशी अन्य रिकॉर्ड के अन्तिम के रहित संयुक्त राज्य अमेरिका सम्पन्न होने के बारे में प्रत्येक कही गई।

VI. ऊर्जा उत्सर्जना विश्वासेदेश द्वारा द्वारा उत्पादन के अधीन है और उत्पादन के लिए ऊर्जाका उपयोग का अधिकार दिया जाएगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2007

Auction for Sale (Re-issue) of '8.33 per cent Government Stock, 2036'

F. No. 4(5)-W&M/2007(i).— Government of India hereby notifies sale (re-issue) of '8.33 per cent Government Stock, 2036' (hereinafter called 'the Stock') for an aggregate amount of Rs. 3,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification') as also the terms and conditions specified in the General Notification F No.4 (9)-W&M/2000, dated May 6, 2002 issued by Government of India as amended from time to time.

Method of Issue

2. The Stock will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai- 400 001 in the manner as prescribed in paragraph 5.1 of the General Notification F No.4 (9)-W&M/2000, dated May 6, 2002 by a price based auction using multiple price auction method.

Allotment to Non-competitive Bidders

3. The Government Stock up to 5 per cent of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions as per the enclosed Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities (Annex).

Place and date of auction

4. The auction will be conducted by Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on September 7, 2007. The application form duly filled in with the bids should be submitted to the aforesaid office on September 7, 2007, by 12.30 P.M.

When Issued Trading

5. The Stock will be eligible for "When Issued" trading in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India in its circular No.RBI/2006-07/178 dated November 16, 2006.

Tenure

6. The Stock will be of thirty-year tenure commencing from June 7, 2006. The stock will be repaid at par on June 7, 2036.

Date of issue and payment for the Stock

7. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its Fort, Mumbai office on September 7, 2007. The payment by successful bidders will be on September 10, 2007. i.e., the date of re-issue. The payment for the Stock will include accrued interest on the nominal value of the Stock allotted in the auction from the date of last coupon payment, i.e., June 7, 2007 to September 9, 2007.

Interest

8. Interest at the rate of 8.33 per cent per annum will accrue on the nominal value of the Stock from the date of last coupon payment and will be paid half yearly on December 7 and June 7.

3671 52707-3

By Order of the President of India

V. SIVASUBRAMANIAN, Director (Budget)

Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities

I. Seppe: With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government securities it is proposed to allow participation on "non-competitive" basis in *select* auctions of dated Government of India (GOI) securities. Accordingly, non-competitive bids *up to 5 per cent* of the notified amount will be accepted in the auctions of dated securities. The reserved amount will be **within** the notified amount.

II. Eligibility: Participation on a non-competitive basis in the auctions of dated GOI Securities will be open to investors who satisfy the following:

1. do not maintain current account (CA) or Subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India.

Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks shall be covered under this Scheme in view of their statutory obligations.

2. make a *single* bid for an amount not more than Rs. two crore (face value) per auction.
3. submit their bid *indirectly* through any *one* bank or PD offering this scheme.

Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks that maintain SGL account and current account with the Reserve bank of India shall be eligible to submit their non competitive bids directly.

III. Coverage: Subject to the conditions mentioned above, participation on "non-competitive" basis is open to any person including firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts, and any other entity as may be prescribed by RBI. The minimum amount for bidding will be Rs. 10,000 (face value) and thereafter in multiples in Rs. 10,000 as hitherto for dated stocks.

IV. Other Operational Guidelines:

1. It will *not* be mandatory for the retail investor to maintain a constituent subsidiary general ledger (CSGL) account with the bank or PD through whom they wish to participate. However, an investor can make only a single bid under this scheme. An undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to be obtained and kept on record by the bank or PD.

2. Each bank or PD on the basis of firm orders received from their constituents may submit application -wise bids through NDS. The firm orders received from others (i.e. non-constituents) may be submitted in physical application forms to the PDO. The physical application may be a single bid for the aggregate amount of all the customers. Particulars of individual customer viz. name and amount shall be provided as an Annex to the bid.

3. Allotment under the non-competitive segment to the bank or PD will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the bank or PD against payment on the date of issue irrespective of whether the bank or PD has received payment from their clients.

4. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5% of notified amount), pro rata allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.

5. In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion.

6. Security would be issued *only* in SGL form by RBI. RBI would credit either the main SGL account or the CSGL account of the bank or PD as indicated by them. The facility for affording credit to the main SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents. Therefore, the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the non-competitive bids the amounts (*face value*) to be credited to their SGL account and the CSGL account. Delivery in physical form from the main SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently.

7. It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients. Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the clients shall be completed within *five* working days from the date of issue.

8. The bank or PD can recover upto six paise per Rs100 as brokerage/commission/service charges for rendering this service to their clients. Such costs may be built into the sale price or recovered separately from the clients. In case the transfer of securities is effected subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the bank or PD would also include accrued interest from the date of issue.

9. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest wherever applicable and brokerage/commission/service charges may be worked out by the bank or PD as per agreement with the client. It may be noted that no other costs such as funding costs should be built into the price or recovered from the client.

V. Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank.

VI. The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified.
